प्रेम चंद पंडित, जे. के समक्ष

सहज राम और अन्य

अपीलीय सिविल, - अपीलकर्ता
बनाम

सॉर्टी और अन्य, -

प्रतिवादी नियमित द्वितीय अपील संख्या 624

1966 दिसंबर 1, 1969

पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट (1961 का XVIII)-धारा 2 (जी) (3) और 2 (जी) (5)-बंजर कादिम-राजस्व रिकॉर्ड में दिखाई गई भूमि जो कि थोला के शामलात के स्वामित्व में है और उसके मालिक के पास है-ऐसी भूमि-चाहे वह धारा 2 (जी) (3) या 2 के तहत आती है।(g) 5-धारा 2 (छ) (5) के अंतर्गत आने वाली भूमि-क्या इसका उपयोग गाँव के सामान्य प्रयोजनों के लिए शामलत देह बनने के लिए दिखाया जाना है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि को पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 (छ) (5) के दायरे में लाने के लिए तीन बातें स्थापित की जानी चाहिए (1) कि भूमि को बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है (2) कि इसका उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाँव के सामान्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है और (3) कि गाँव के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक गाँव में शमिलात देह मौजूद नहीं है। भूमि शमिलात देह या शामलात थोला के स्वामित्व में हो सकती है, लेकिन यदि इसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया जाता है, तो यह धारा 2 (जी) (5) द्वारा शासित होगी यदि यह दिखाया जा सकता है कि इसका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। एक व्यक्तिगत मालिक की हिस्सेदारी में कुछ भूमि भी शामिल हो सकती है जिसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे शामलत देह में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इसका उपयोग गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया होगा। यह इस प्रकार है कि यदि स्वामी के कॉलम में, भूमि को शामलात देह या शामलात थोला के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में इसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है, तो अधिनियम की धारा 2 (छ) का खंड (5) ऐसी भूमि के लिए लागू होगा, यदि यह आगे दिखाया जाता है कि इसका उपयोग गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह खंड विशिष्ट होने के कारण धारा के सामान्य खंड (3) को बाहर कर देगा।

श्री डी. आर. सैनी, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के न्यायालय के डिक्री से नियमित दूसरी अपील, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ, रोहतक, दिनांक 16 फरवरी, 1966, श्री एस. डी. त्यागी, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, झज्जर, दिनांक 19 जनवरी, 1965 की लागत के साथ पुष्टि करते हुए, वादी के वाद को खारिज करते हुए।

एस. पी. जे. एन, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

यू. डी. गोर, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

पंडित, जे. -यह दूसरी अपील रोहतक जिले के गाँव रोहड़ के रहने वाले सहज राम और तीन अन्य लोगों द्वारा मान सिंह और उसी गाँव के अन्य लोगों के खिलाफ इस आशय की घोषणा के लिए दायर मुकदमे से उत्पन्न होती है कि उस गाँव में स्थित 537 कनाल 1 मरला की कृषि भूमि ग्राम पंचायत की संपत्ति थी और प्रतिवादियों को इसे विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं था। उनके आरोप थे कि उक्त भूमि तोला रामियन की शामलात थी। यह 26 जनवरी, 1950 तक बंजर में पड़ा था और इसका उपयोग पूरे गाँव के सामान्य लाभ के लिए किया जा रहा था। 1955 के बाद, इसके एक हिस्से को वादी सहित कुछ मालिकों द्वारा खेती के तहत लाया गया था। पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे इसके बाद 1961 अधिनियम कहा

जाता है, भूमि 'शामलात देह' की परिभाषा के अंतर्गत आती है और ग्राम पंचायत में निहित होती है। तोला रामियन के मालिकों का भूमि से कोई संबंध नहीं था। हालाँकि, प्रतिवादियों ने भूमि के विभाजन के लिए राजस्व अधिकारी को आवेदन दिया। वादी ने आपत्ति जताई कि चूंकि भूमि ग्राम पंचायत में निहित है, इसलिए इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। राजस्व अधिकारी ने 7 दिसंबर, 1963 को भूमि का विभाजन करने का आदेश दिया। इसके कारण जनवरी, 1964 में वर्तमान मुकदमा दायर करना आवश्यक हो गया। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ग्राम सभा, रोहत और ग्राम पंचायत, रोहत को प्रतिवादी संख्या44 और 45 के रूप में शामिल किया गया था।

(2) कुछ प्रतिवादियों द्वारा वाद का विरोध किया गया था और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अनुरोध किया कि विचाराधीन भूमि पूरे गांव के लाभ के लिए आवश्यक नहीं थी; इसका वह हिस्सा थोला के कुछ मालिकों द्वारा खेती की जा रही थी और शेष थोला के पूरे स्वामित्व निकाय के संयुक्त कब्जे में था; कि भूमि ग्राम पंचायत में निहित नहीं थी, क्योंकि यह 'शमिलात देह' की परिभाषा के भीतर नहीं आती थी; और यह कि वादी के पास मुकदमा लाने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी तरह से ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। यह भी कहा गया था कि मुकदमा वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं था।

(3) विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चूंकि वादी स्वयं विचाराधीन भूमि पर किसी अधिकार का दावा नहीं कर रहे थे और उनका मामला यह था कि यह ग्राम पंचायत में निहित था, इसलिए उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के तहत एक घोषणात्मक मुकदमा लाने का कोई अधिकार नहीं था और यह वर्तमान रूप में नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विवादित भूमि 1961 के अधिनियम में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर 'शमिलात देह' नहीं थी और इसलिए यह ग्राम पंचायत में निहित नहीं थी। प्रतिवादियों के पास थोला रामियन के मालिक के रूप में भूमि का कब्जा था और इसलिए, वे उक्त भूमि के विभाजन का दावा कर सकते थे। इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

(4) उस निर्णय से व्यथित होकर, वादी ने वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष अपील की, जिन्होंने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। वादी दूसरी अपील में इस न्यायालय में आए हैं।

(5) मेरे सामने दो प्रश्नों पर बहस की गई। पहला वाद को वर्तमान रूप में लाने के लिए वादी के अधिकार क्षेत्र के बारे में था और दूसरा यह था कि क्या विवादित भूमि 'शमिलात देह' थी और ग्राम पंचायत में निहित थी, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो निस्संदेह प्रतिवादी इसे विभाजित नहीं कर सकते थे।

(6) जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, यह स्वीकार किया जाता है कि वादी तोला रामियन में स्वामी थे, जिसमें विचाराधीन भूमि स्थित थी और इसलिए, भूमि में उनका निश्चित हित था। उनका मामला यह था कि उक्त भूमि 'शमिलात देह' की परिभाषा के भीतर आई थी और इसलिए, यह ग्राम पंचायत में निहित थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी, जो उस तोला के मालिक भी थे, इसे विभाजित नहीं कर सके। यह सच है कि ग्राम पंचायत को मुकदमा लाना चाहिए था, क्योंकि जमीन उसमें निहित थी। लेकिन वर्तमान वाद में वादी का आरोप था कि पंचायत प्रतिवादियों के साथ मिली-जुली थी और स्वामित्व निकाय के हितों की रक्षा नहीं कर रही थी। वादी की आपत्ति के बावजूद राजस्व अधिकारी ने निर्णय लिया था कि प्रतिवादियों के कहने पर उक्त भूमि का विभाजन किया जा सकता है। चूंकि स्वामित्व का प्रश्न उठा था और यह सिविल न्यायालय को तय करना था कि विवादित भूमि आंशिक थी या नहीं, इसलिए वादी ने उस उद्देश्य के लिए मुकदमा दायर किया था। उनके लिए यह आरोप लगाना और साबित करना आवश्यक नहीं था कि जमीन केवल उनकी थी। यदि ग्राम पंचायत अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी तो वे प्रतिनिधि क्षमता में इस प्रकृति के सूट को लाकर पूरे स्वामित्व निकाय के हितों की रक्षा कर सकते थे। इन परिस्थितियों में, निचली अदालतों ने कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं था और आगे यह कि यह वर्तमान रूप में नहीं था। इसलिए, मैं इस बिंदु पर उनके निष्कर्ष को उलट दूंगा और मानूंगा कि वादी को वर्तमान रूप में मुकदमा लाने का अधिकार था।

(7) अब दूसरे प्रश्न पर आते हुए, कि क्या विवादित भूमि 'शमिलात देह' थी और पंचायत में निहित नहीं थी, नीचे दिए गए न्यायालयों ने वादी के इस तर्क को नकार दिया था कि भूमि थोला रामियन की 'शमिलात' थी और इसका उपयोग थोला के मालिकों के सामान्य लाभ के लिए किया जा रहा था और यह 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) (3) की परिभाषा के भीतर आया था और ग्राम पंचायत में निहित था। निम्नलिखित न्यायालयों का विचार था कि धारा 2 (छ) का खंड (3) वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि बंजर कादिम थी। उनके अनुसार, उसी धारा का खंड (5) लागू होगा और चूंकि वादी यह स्थापित करने में सक्षम नहीं थे कि भूमि का उपयोग राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था और आगे यह कि 'शमिलात देह' गांव के कुल क्षेत्र के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक गांव में मौजूद नहीं था, यह उस खंड में दी गई 'शमिलात देह' की परिभाषा के भीतर नहीं आता था और इसके परिणामस्वरूप, यह ग्राम पंचायत में निहित नहीं था।

(8) अपीलार्थियों के वकील ने प्रथम दृष्टांत में यह तर्क दिया कि विवादित भूमि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1953 (1954 का पंजाब अधिनियम I) के प्रवृत्त होने पर गांव पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत में निहित थी, जिसे इसके बाद 9 जनवरी, 1954 को 1954 अधिनियम कहा जाता है। तत्पश्चात, 1954 के अधिनियम को 1961 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था और बाद के अधिनियम की धारा 4 (2) के आधार पर, उक्त भूमि को 1961 के अधिनियम के तहत पंचायत में निहित माना जाएगा।

(9) अपीलार्थियों के इस तर्क को स्वीकार करने में कई कठिनाइयाँ होंगी। सबसे पहले, यह मामला कभी भी वाद में अपीलार्थियों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था और इसकी सुनवाई नीचे दिए गए न्यायालयों में नहीं की गई थी। इसे इस न्यायालय में अपील के आधार में भी जगह नहीं मिलती है। दूसरा, 1954 अधिनियम की धारा 3 के तहत, यह गाँव का 'शमिलात देह' था, जो पंचायत में निहित होगा। माना जा सकता है कि विवादित भूमि 'शमिलात तोला रामियां' है न कि 'शमिलात देह'। तीसरा, 1954 के अधिनियम के तहत 'शमिलात देह' को 'नियत तिथि' पर पंचायत में निहित करना था। उस अधिनियम की धारा 2 (3) में 'नियत तिथि' को इस प्रकार परिभाषित किया गया था कि "किसी गांव के मामले में, जो इस अधिनियम के प्रारंभ में पंचायत की अधिकारिता के अधीन है, ऐसे प्रारंभ की तारीख होगी; और अन्य मामलों में, वह तारीख जिस पर उस गांव पर अधिकारिता वाली पंचायत का गठन किया जाता है। अभिलेख पर, वर्तमान मामले में, यह सिद्ध नहीं किया गया है कि क्या गाँव रोहड़, जिसमें विवादित भूमि स्थित है, 1954 के अधिनियम के प्रारंभ में पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अधीन था और आगे यदि वह गाँव पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं था, जिस तारीख को गाँव पर अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत का गठन किया गया था। चौथा, यह मानते हुए भी कि विवादग्रस्त भूमि 1954 के अधिनियम के अधीन, 1961 के अधिनियम की धारा 3 (2) के उपबंधों के आधार पर पंचायत में निहित थी, ऐसी भूमि में पंचायत के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित 1961 के अधिनियम के प्रारंभ से समाप्त हो जाएंगे, यदि उस भूमि को 1961 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित 'शमिलात देह' से बाहर रखा गया है और उन अधिकारों, स्वामित्व और हित को उस व्यक्ति या व्यक्तियों में संशोधित किया जाएगा जिसमें उन्होंने 1954 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले तत्काल निहित किया था।

(10) तब यह प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन भूमि ने 1961 के अधिनियम की धारा 2 (छ) (3) में दिए गए 'शमिलात देह' के विवरण का उत्तर दिया था और इसलिए, ग्राम पंचायत में निहित था और नीचे दिए गए न्यायालयों ने गलती से इसके विपरीत अभिनिर्धारित किया था।

(11) आइए अब हम जाँच करें कि क्या इस उप-मिशन में कोई सार है। नाथू और अन्य बनाम पूरन और अन्य (1) वाले मामले में न्यायमूर्ति डी. के. महाजन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1961 के अधिनियम की धारा 3 ने अपनी धारा 2 के खंड (छ) में 'शमिलात देह' की परिभाषा को उन मामलों पर भी लागू किया जो 1954 के अधिनियम के अधीन उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा, 1961 के अधिनियम की धारा 3 की वह उपधारा (1) संभावित और पूर्वव्यापी दोनों थी और इसलिए, 1954 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कौन सी भूमि 'शमिलात' भूमि थी, इसका पता लगाने के लिए धारा 2 (छ) को 1954 के अधिनियम में पढ़ा जाना था। इस फैसले को डी. के. महाजन और आर. एस. नरूला जे. जे. की पीठ के बाद के फैसले में मंजूरी दी गई थी। लाखीराम बनाम ग्राम पंचायत गुडा

में, नाथू और अन्य के मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि (वह समय जब 1954 के अधिनियम या 1961 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शमिलात भूमि की प्रकृति निर्धारित की जानी थी, वह 9 जनवरी, 1954 था, 1954 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख, जैसा कि बाद के अधिनियम की धारा 2 (ज) में परिभाषित किया गया है, न कि 4 मई, 1961,1961 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख। पक्षों के वकील ने इन दो निर्णयों की शुद्धता को चुनौती नहीं दी और इसलिए, मैं इन अधिकारियों में निर्धारित कानून को तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

(12) 9 जनवरी, 1954 को विवादित भूमि की प्रकृति क्या थी और क्या यह 1961 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (छ) में दी गई 'शमिलात देह' की परिभाषा के अंतर्गत आती है? 1941-42 की जामबंदी, प्रदर्शनी पृष्ठ 4 है, जो इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए एकमात्र प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड है। इसमें स्वामित्व स्तंभ में भूमि को तोला रामियन की शमिलात के रूप में दिखाया गया है। इसे मकबूज़ा मलिकन, i.e के रूप में दर्ज किया गया है। उस तोला के स्वामियों के अधिकार में। इसके अलावा इस भूमि को बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी भूमि के लिए, 1961 अधिनियम की धारा 2 (छ) का खंड (3), जैसा कि अपीलार्थियों के वकील द्वारा प्रतिवाद किया गया है, उसी धारा के खंड (5) द्वारा लागू होगा या इसके अंतर्गत आएगा, जैसा कि प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा तर्क दिया गया है, खंड (3) और (5) पढ़ें -

"2. (छ) "शमिलात देह" में शामिल हैं-(1) से (2) * * * * * * (3) राजस्व अभिलेखों में शमिलात, तराफ, पट्टी, पन्ना और थोला के रूप में वर्णित भूमि और जिसका उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम समुदाय या उसके किसी भाग के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है; (4) * * * * * * (5) किसी गाँव में बंजर कादिम के रूप में वर्णित भूमि और राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाँव के सामान्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैः

बशर्ते कि गाँव के कुल क्षेत्र के कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक शमिलात देह गाँव में मौजूद नहीं है; लेकिन इसमें ऐसी भूमि शामिल नहीं है जो-(i) से (iv) * * * (v) राजस्व अभिलेखों में शमिलात तरफ, पट्टियों, पन्ना अफिद तोला के रूप में वर्णित है और राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम समुदाय या उसके एक हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की जाती है;

(13) अपीलार्थियों के वकील का तर्क था कि भूमि को राजस्व अभिलेखों में तोला रामियन की शमिलात के रूप में दर्ज किया गया था और इसका उपयोग राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम समुदाय के एक हिस्से के लाभ के लिए किया गया था, क्योंकि यह उस तोला के मालिकों के कब्जे में था। इसलिए, यह खंड द्वारा कवर किया गया था (3). इस निवेदन के लिए उन्होंने को-ऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ शमिलात पट्टी हरनाम सिंह, ग्राम खन्नी के लामबरदार और ग्राम खन्नै (3) की एक अन्य ग्राम पंचायत में न्यायमूर्ति डी. के. महाजन के निर्णय पर अपना भरोसा रखा, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि राजस्व अभिलेखों में कुछ भूमि 'शमिलात पट्टी' के रूप में दर्ज की गई थी और उसके मालिकों के कब्जे में थी, तो उस प्रविष्टि से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि विचाराधीन शमिलात का उपयोग ग्राम समुदाय के एक हिस्से के लाभ के लिए किया जा रहा था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि शमिलात के मालिकों में से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से लाभ का जुर्माना लगाया गया था। यह लाभ संयुक्त रूप से पट्टी के सभी मालिकों को गया और इसलिए, वह भूमि 'शमिलैक-थफ 1961 अधिनियम' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती थी और पंचायत में निहित थी।

(14) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि को बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया था और ऐसा होने पर, खंड (5) जो विशेष रूप से ऐसी भूमि से संबंधित था, लागू हुआ और उसमें उल्लिखित परिभाषा को संतुष्ट किया जाना था इससे पहले कि ऐसी भूमि को 'शमिलात देह * कहा जाए।

(15) पक्षकारों के वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने में योग्यता है। थोला के शमिलात में विभिन्न प्रकार की भूमि शामिल हो सकती है। यह बंजर कादिम, बंजर जादिद, घैर मुम्किन बरानी, नेहरी, रोज़ली आदि हो सकते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार की भूमि को शमिलात थोले में शामिल

किया जा सकता है। दूसरी ओर, खंड (6) केवल उन भूमि से संबंधित है जिन्हें बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है। वे शमिलात देह या शमिलात थोला के स्वामित्व में हो सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया जाता है, तो वे खंड (5) द्वारा शासित होंगे और उन्हें 'शमिलात देह' कहा जाएगा, अगर यह दिखाया जा सकता है कि उनका उपयोग किया गया था राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए। एक व्यक्तिगत मालिक की होल्डिंग में कुछ भूमि भी शामिल हो सकती है जिसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन इसे शमिलात देह में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इसका उपयोग गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया होगा। यह इस प्रकार है कि यदि स्वामी के कॉलम में, भूमि को शमिलात देह या शमिलात थोला के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन राजस्व अभिलेखों में इसे बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया है, तब खंड (5) लागू होगा और ऐसी भूमि के लिए वह खंड विशिष्ट और खंड (3) सामान्य होगा। विशिष्ट, निस्संदेह, सामान्य को बाहर कर देगा। ऐसा होने पर, नीचे दिए गए न्यायालयों ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया कि वादी तभी सफल हो सकते हैं जब वे यह दिखा सकें कि विवादित भूमि खंड द्वारा कवर की गई थी (5). ऐसा करने के लिए, तीन चीजें स्थापित करनी थीं-(1) भूमि को बंजर कादिम के रूप में वर्णित किया गया था; (2) इसका उपयोग राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था; और (3) यह प्रावधान किया गया था कि गाँव के कुल क्षेत्र के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक गाँव में शमिलात देह मौजूद नहीं था। केवल शर्त नं. (1) तत्काल मामले में संतुष्ट था। राजस्व अभिलेखों के अनुसार यह नहीं दिखाया गया था कि भूमि का उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1962 में निर्णय P.L.R. 730 अपीलार्थियों के लिए किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि भूमि को थोला के स्वामी के कब्जे में दर्ज किया गया था, तो यह कहा जाएगा कि इसका उपयोग ग्राम समुदाय के 9 भाग के लिए किया जा रहा था। रेखांकित शब्द खंड में नहीं आते हैं (5). इसके तहत, यह स्थापित किया जाना था कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बंजर कादिम भूमि का उपयोग गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। आगे की शर्त नं. (3) अपीलार्थियों द्वारा भी पूरा नहीं किया गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि तर्कों के दौरान, यह भी सुझाव दिया गया था कि खंड (5) के अंत में आने वाले परंतुक में ऊपर वर्णित सभी खंड (1) से (5) शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में इस प्रश्न को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

(16) इसलिए, मैं यह अभिनिर्धारित करूँगा कि नीचे दिए गए न्यायालय प्रश्नगत भूमि पर खंड (5) को लागू करने और यह विनिश्चय करने में सही थे कि उस खंड में उल्लिखित आवश्यक शर्तों को वादी द्वारा संतुष्ट नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, भूमि शमिलात देह नहीं थी, जो पंचायत में निहित हो सकती थी।

(17) यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि ऊपर निर्दिष्ट धारा 2 (छ) के खंड (v) द्वारा कवर की गई थी, और इसलिए, शमिलात देह में शामिल नहीं की जाएगी। उनका तर्क था कि हालांकि राजस्व अभिलेखों में भूमि को शमिलात थोला के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन राजस्व अभिलेखों के अनुसार इसका उपयोग ग्राम समुदाय या उसके एक हिस्से के लाभ के लिए या गाँव के सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था। अपीलार्थियों का तर्क, 1962 P.L.R में महाजन, जे. के निर्णय के आधार पर। 730 कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि का उपयोग ग्राम समुदाय के एक भाग के लाभ के लिए किया गया था, क्योंकि यह दिखाया गया था कि यह तोला रामियन के मालिकों के कब्जे में था, उनके अनुसार, बिना किसी उप-रुख के था। विद्वान वकील ने निर्णय की शुद्धता को चुनौती दी बिक्कर सिंह बनाम पंजाब राज्य (कोशल, जे.) महाजन, जे. के बारे में, क्योंकि उनके अनुसार, यदि उस थोले की शमिलात अकेले थोले के मालिकों के कब्जे में थी, तो यह नहीं कहा जा सकता था कि इसका उपयोग ग्राम समुदाय के एक हिस्से के लाभ के लिए किया जा रहा था। यह दिखाया जाना चाहिए कि उस विशेष थोले के मालिकों के अलावा गाँव के लोगों को उक्त भूमि से कुछ लाभ मिल रहा था, इससे पहले कि यह माना जा सके कि इसका उपयोग गाँव के समुदाय के एक हिस्से के लाभ के लिए किया जा रहा था, क्योंकि यदि थोले के मालिक स्वयं उस भूमि के कब्जे में थे और इसे अपने लिए उपयोग कर रहे थे, तो वे केवल अपने स्वयं के अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए वे भूमि में कानूनी रूप से हकदार थे। यह साबित किया जाना चाहिए कि अन्य ग्रामीण, जिनके पास उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं था, वे भी इसका उपयोग कर रहे थे या भूमि का उपयोग उनके कल्याण के लिए भी किया जा रहा था, इससे पहले कि यह कहा जा सके कि इसका

उपयोग ग्राम समुदाय के एक हिस्से के लाभ के लिए किया गया था। तथापि, इस मामले का विनिश्चय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, जैसा कि पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित किया जा चुका है, वादी यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुए हैं कि भूमि 1961 अधिनियम की धारा 2 (छ) के खंड (1) से खंड (5) में से किसी के भीतर 'शमिलात देह' थी।

(18) जो मैंने ऊपर कहा है, उसे देखते हुए यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, इस मामले की परिस्थितियों में, मैं पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)